

ऑनलाइन सर्टफिकेट ऑफ ओरजिन फॉर मर्चेंडाईज एक्सपोर्ट

प्रलिस के लयि:

सर्टफिकेट ऑफ ओरजिनि (CoO), ट्रेड एग्रीमेंट के प्रकार ।

मेन्स के लयि:

नरियात प्रोत्साहन योजनाएँ और भारत द्वारा हस्ताक्षरति व्यापार समझौतों का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

केंद्र ने 31 जनवरी 2022 तक नरियातकों पर प्रत्येक आउटबाउंड खेप के लयि सर्टफिकेट ऑफ ओरजिनि (CoO) प्राप्त करने के लयि अनविर्य दायतिव को नलिबति कर दया है । .

प्रमुख बदि:

परचिय:

- जनि देशों के साथ भारत का **अधमिनी व्यापार समझौता (PTA)** हुआ था, उन देशों को नरियात के लयि 2019 के अंत में ऑनलाइन CoO प्रणाली को नवंबर 2021 से सभी व्यापारकि नरियात को कवर करने के लयि वसितारति कया गया था ।
- यह मंच सभी नरियातकों, सभी **मुक्त व्यापार समझौतों (FTA)**/अधमिन्त्य व्यापार समझौतों (PTA) और सभी संबधति एजेंसयिों के लयि एकल पहुँच बदि के रूप में कार्य करता है ।

नरिमाण:

- मंच को वदिश व्यापार महानदिशक (DGFT) तथा कषेत्रीय और बहुपक्षीय व्यापार संबध (RMTR) डविजन, वाणज्य वभिग, वाणज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा डजिाइन एवं वकिसति कया गया है ।

महत्त्व:

- यह ऑनलाइन सुवधि नरियातक समुदाय को 'व्यापार करने में आसानी' प्रदान करती है और एक क्यूआर कोड के माध्यम से जारी कयि गए CoO की वास्तवकिता की पुष्टिकरने के लयि भागीदार देशों को एक सत्यापन योग्य प्रमाणीकरण तंत्र प्रदान करती है जो जारी कयि गए ई-CoO में वशि्वसनीयता को जोडती है ।

मर्चेंडाईज एक्सपोर्ट की स्थति:

- भारत का मासकि व्यापारकि नरियात लगातार सात महीनों में 30 बलियिन अमेरकि डॉलर को पार कर गया है और 2021-22 में सरकार के रकिॉर्ड 400 बलियिन अमेरकि डॉलर के लक्ष्य तक पहुँचने के लयि काफी हद तक प्रतबिध है ।
 - मर्चेंडाईज एक्सपोर्ट एक वदिशी उपभोक्ता बाज़ार में बकिरी के लयि खुदरा सामान की पेशकश करने की एक वधि है ।

भारत की नरियात प्रोत्साहन योजनाएँ:

मर्चेंडाईज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम:

- **MEIS** को वदिश व्यापार नीति(FTP) 2015-20 में पेश कया गया था, MEIS के तहत, सरकार उत्पाद और देश के आधार पर शुल्क लाभ प्रदान करती है ।

सर्वसि एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम:

- इसके तहत वाणज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत में स्थति सेवा नरियातकों को भारत से सेवाओं के नरियात को बढ़ावा देने के लयि प्रोत्साहन दया जाता है ।

'नरियात उत्पाद पर शुल्क या करों की छूट' (RoDTEP) योजना:

- यह भारत में नरियात बढ़ाने में मदद करने हेतु **'वस्तु और सेवा कर'** में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लयि पूरी तरह से स्वचालति मार्ग है ।
- इसे जनवरी 2021 में MEIS के प्रतस्थिापन के रूप में शुरू कया गया था, जो **वशि्व व्यापार संगठन** के नयिमों के अनुरूप नहीं था ।

राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट (RoSCTL):

- RoSCTL को मार्च 2019 में ऐसे राज्य और केंद्रीय एम्बेडेड शुल्क एवं करों हेतु पेश कया गया था, जो वस्तु और सेवा कर (GST) के माध्यम से वापस नहीं कयि जाते हैं ।

- यह केवल कपड़ों और मेड-अप्स के लिये उपलब्ध है। इसे कपड़ा मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था।
 - इससे पूर्व इसे 'रबिट फॉर स्टेट लेवीज़' (ROSL) के नाम से जाना जाता था।

व्यापार समझौतों के प्रकार

- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):**
 - FTA के तहत दो देशों के बीच आयात-नरियात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदिको सरल बनाया जाता है।
 - 'मुक्त व्यापार समझौता' एक ऐसा समझौता है जिसमें दो या दो से अधिक देश एक दूसरे को सरल व्यापार शर्तें, टैरिफ रियायत आदि प्रदान करने हेतु सहमत होते हैं।
 - भारत ने कई देशों, जैसे- श्रीलंका के साथ-साथ वभिन्न व्यापारिक समूहों यथा- आसियान (ASEAN) से FTA पर बातचीत की है।
- **अधिमिन्य व्यापार समझौता (PTA):**
 - PTAs या **सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली** (GSP) वभिन्न देशों द्वारा व्यापार के संबंध में अपनाई गई एक विशेष स्थिति है। इस प्रकार के समझौते में, दो या दो से अधिक भागीदार एक नश्चिती संख्या में टैरिफ लाइनों पर शुल्क को कम करके कुछ उत्पादों को प्रवेश का अधिमिन्य अधिकार देते हैं।
 - अधिमिन्य व्यापार समझौते में भी कुछ उत्पादों पर शुल्क घटाकर शून्य किया जा सकता है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA):**
 - 'व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता' FTA से अधिक व्यापक होता है।
 - इस समझौते के अंतर्गत सेवाओं, निवेश और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों में व्यापार को कवर किया जाता है।
 - भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किये हैं।
- **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA):**
 - CECA आमतौर पर व्यापार प्रशुल्क और TRQ (टैरिफ दर कोटा) दरों को कवर करता है। यह व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता की तरह व्यापक नहीं है। भारत ने मलेशिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किये हैं।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/online-certificate-of-origin-for-merchandise-export>

